

भोपाल। यूनाइटेड
डाक्टर्स फॉरम, नरसिं
हा सेवा संसिद्धिएशन और
और ईडेंस मेंडिकल
एसोसिएशन (आइएमए)
ने नरसिंह होम एक्ट में
बदलाव का विरोध किया



नरसिंह होम एक्ट में बदलाव का विरोध

है। उनका कहना है कि उनकी राय लिए बिना मनमाने ढंग से बदलाव कर दिया गया है। पंजीयन की पीस बढ़ा दी गई है। इसका असर मरीजों पर पड़ेगा। सबसे ज्यादा विरोध एक रेसीटेंट डाक्टर के सिर्फ एक जाह काम करने से आवश्यक था। उनके असर नागरिक आदृति नियम ने इस गेहूं को किया की बिक्री की है। तीन लाख टन गेहूं के उत्तरव के अनुबंध भी हो चुके हैं। यह गेहूं कमल नाथ सरकार के समय में खरीदा गया था। तब सरकार ने किसान समर्पित योजना प्रांभ करके किसानों को प्रति क्रिंटल 165 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। इसे केंद्र सरकार ने बोनस मानते हुए सेंटल पूल में लेने से मन कर दिया था। काफी मान-मनोव्यवल के बाद भी जब बात नहीं खोल सकेंगे। इसी तरह एक रेसीटेंट डाक्टर आयुष के नरसिंह होम नहीं खोल सकेंगे। इसी तरह एक रेसीटेंट डाक्टर आयुष के नरसिंह होम नहीं दे पाएगा। ऐसे में कोई भी डाक्टर मध्यप्रदेश में काम करने करेगा। जहां उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, वहां जाएगा। अस्पताल डाक्टर को ज्यादा बेतन देंगे तो इसका भी अप्रत्यक्ष रूप से भार मरीज पर ही आएगा।

-D. अनन्प हजेला, अध्यक्ष यूनाइटेड डाक्टर्स फॉरम

अब यह व्यवस्था कर दा गई है नाना डाक्टर या स्टाफ रखने के बाद तीन दिन के भीतर योग्यप्रदेशी को मूचना देनी होगी। अब हम लोग स्टाफ की भर्ती करने के बाद कोई भी मरीज नाना भर उसका काम देखते हैं। इसके बाद ही नियमित करते हैं। 20 बिस्तर पर चार नर्स रखने की व्यवस्था भी कठिन है। इस प्रविधान में कुछ गफलत लग रही है। फोस भी बढ़ा दी गई है।

मानदेय घोटाला-दोषियों को वलीनचिट देने वाले अफसरों की जांच

भोपाल जिले की आठ बाल विकास परियोजनाओं ने सबसे पहले घोटाला पकड़ में आया

भोपाल। अपांगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय घोटाले की जांच कर बलीनचिट दे चुके तीन अफसरों की जांच के लिए नई समिति बना दी गई है। यह समिति पुराने जांच प्रतिवेदों का परीक्षण करी और संबंधित के बायान लेकर शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। मध्य प्रदेश के बायान लेकर ज्यादा जारी रहा। 25 करोड़ रुपये से अधिक के मानदेय घोटाले में अब बड़े अधिकारी फसले रिपोर्ट दे रहे हैं। पहली बार उन अधिकारियों की जांच के लिए समिति बनाई गई है, जिन्होंने मानदेय घोटाले को शिकायत की जांच में फर्जी बताकर आरोपितों को बलीनचिट दे दी थी। भोपाल जिले की आठ बाल विकास परियोजनाओं में सबसे पहले घोटाला पकड़ में आया। यहां प्रेसों में सबसे ज्यादा साड़े छह करोड़ का घोटाला हुआ है। भारतीयों की जांच के लिए नई समिति बनाई गई है।

राज्य नागरिक आदृति नियम पर बढ़ते जा रहे कज के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने छह लाख 43 हजार टन गेहूं को सेंटल पूल में लेने से मना कर दिया था, उसे प्रदेश सरकार ने लागवा 12 सौ करोड़ रुपये में बेचा है। खुले बाजार में नीलामी के माध्यम से राज्य नागरिक आदृति नियम ने इस गेहूं को किया की बिक्री की है। तीन लाख टन गेहूं के उत्तरव के अनुबंध भी हो चुके हैं। यह गेहूं कमल नाथ सरकार के समय में खरीदा गया था। तब सरकार ने किसान समर्पित योजना प्रांभ करके किसानों को प्रति क्रिंटल 165 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। खरीद के बाय जब सेंटल पूल में गेहूं देने की बात आई तो केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति उठाई। दूसरी बार, केंद्र सरकार के बीच अनुबंध है कि खरीद के पहले ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, जिसका बाजार पर विपरीत असर पड़े। जबकि, प्रेस सरकार का तर्क था कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राशि दी जा रही है पर केंद्र सरकार इससे सहमत नहीं हुई।

राज्य नागरिक आदृति नियम पर बढ़ते जा रहे कज के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने छह लाख 43 हजार टन गेहूं को नीलाम करने का फैसला किया। नियम ने पहले दो लाख टन गेहूं नीलाम करने के लिए निविदा निकाली पर शर्तों को लेकर विवाद हो गया और सरकार ने पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। इसके बाद छोटे-छोटे समूह बनाकर गेहूं नीलाम करने का कदम उठाया गया। इस प्रयास को सफलता मिली और अपनाएक हजार 875 रुपये प्रति क्रिंटल की दर प्राप्त हुई, जो समर्थन मूल्य से अधिक है। अधिकारी गेहूं की गोदामों से उत्तरव करने के लिए अनुबंध हो गया है। नियम ने गेहूं की बिक्री से लागवा एक बायान देकर गेहूं नीलाम करने का बुगतान करने के बाद गेहूं के भंडारण, परिवहन सहित अन्य कारों में बड़ी राशि व्यह होती है।

राज्य नागरिक आदृति नियम पर बढ़ते जा रहे कज के बोझ को कम करने के लिए नई समिति बनाई गई है, जिन्होंने मानदेय घोटाले को शिकायत की जांच में फर्जी बताकर आरोपितों को बलीनचिट दे दी थी। भोपाल जिले की आठ बाल विकास परियोजनाओं में सबसे ज्यादा साड़े छह करोड़ का घोटाला हुआ है। भारतीयों की जांच के लिए नई समिति बनाई गई है, जिन्होंने मानदेय घोटाले को शिकायत की जांच करने के लिए नई समिति बनाई गई है। अब यह व्यवस्था कर दा गई है नाना डाक्टर या स्टाफ रखने के बाद तीन दिन के भीतर योग्यप्रदेशी को मूचना देनी होगी। अब हम लोग स्टाफ की भर्ती करने के बाद कोई भी डाक्टर मध्यप्रदेश में काम करने करेगा। जहां उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, वहां जाएगा। अस्पताल डाक्टर को ज्यादा बेतन देंगे तो इसका भी अप्रत्यक्ष रूप से भार मरीज पर ही आएगा।

राज्य नागरिक आदृति नियम पर बढ़ते जा रहे कज के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने छह लाख 43 हजार टन गेहूं को नीलाम करने का फैसला किया। नियम ने पहले दो लाख टन गेहूं नीलाम करने के लिए निविदा निकाली पर शर्तों को लेकर विवाद हो गया और सरकार ने पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। इसके बाद छोटे-छोटे समूह बनाकर गेहूं नीलाम करने का कदम उठाया गया। इस प्रयास को सफलता मिली और अपनाएक हजार 875 रुपये प्रति क्रिंटल की दर प्राप्त हुई, जो समर्थन मूल्य से अधिक है। अधिकारी गेहूं की गोदामों से उत्तरव करने के लिए अनुबंध हो गया है। अधिकारी गेहूं की बिक्री से लागवा एक हजार 200 करोड़ रुपये मिलेंगे। हालांकि, इसके बाद भी यह नियम ने निरस्त कर दिया और अब 12 हजार 80 टन गेहूं की दोबारा नीलामी की जाएगी।

राज्य नागरिक आदृति नियम पर बढ़ते जा रहे कज के बोझ को कम करने के लिए नई समिति बनाई गई है, जिन्होंने मानदेय घोटाले को शिकायत की जांच में फर्जी बताकर आरोपितों को बलीनचिट दे दी थी। भोपाल जिले की आठ बाल विकास परियोजनाओं में सबसे ज्यादा साड़े छह करोड़ का घोटाला हुआ है। भारतीयों की जांच के लिए नई समिति बनाई गई है, जिन्होंने मानदेय घोटाले को शिकायत की जांच करने के लिए नई समिति बनाई गई है। अब यह व्यवस्था कर दा गई है नाना डाक्टर या स्टाफ रखने के बाद तीन दिन के भीतर योग्यप्रदेशी को मूचना देनी होगी। अब हम लोग स्टाफ की भर्ती करने के बाद कोई भी डाक्टर मध्यप्रदेश में काम करने करेगा। जहां उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, वहां जाएगा। अस्पताल डाक्टर को ज्यादा बेतन देंगे तो इसका भी अप्रत्यक्ष रूप से भार मरीज पर ही आएगा।

राज्य नागरिक आदृति नियम पर बढ़ते जा रहे कज के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने छह लाख 43 हजार टन गेहूं को नीलाम करने का फैसला किया। नियम ने पहले दो लाख टन गेहूं नीलाम करने के लिए निविदा निकाली पर शर्तों को लेकर विवाद हो गया और सरकार ने पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। इसके बाद छोटे-छोटे समूह बनाकर गेहूं नीलाम करने का कदम उठाया गया। इस प्रयास को सफलता मिली और अपनाएक हजार 875 रुपये प्रति क्रिंटल की दर प्राप्त हुई, जो समर्थन मूल्य से अधिक है। अधिकारी गेहूं की गोदामों से उत्तरव करने के लिए अनुबंध हो गया है। अधिकारी गेहूं की बिक्री से लागवा एक हजार 200 करोड़ रुपये मिलेंगे। हालांकि, इसके बाद भी यह नियम ने निरस्त कर दिया और अब 12 हजार 80 टन गेहूं की दोबारा नीलामी की जाएगी।

राज्य नागरिक आदृति नियम पर बढ़ते जा रहे कज के बोझ को कम करने के लिए नई समिति बनाई गई है, जिन्होंने मानदेय घोटाले को शिकायत की जांच में फर्जी बताकर आरोपितों को बलीनचिट दे दी थी। भोपाल जिले की आठ बाल विकास परियोजनाओं में सबसे ज्यादा साड़े छह करोड़ का घोटाला हुआ है। भारतीयों की जांच के लिए नई समिति बनाई गई है, जिन्होंने मानदेय घोटाले को शिकायत की जांच करने के लिए नई समिति बनाई गई है। अब यह व्यवस्था कर दा गई है नाना डाक्टर या स्टाफ रखने के बाद तीन दिन के भीतर योग्यप्रदेशी को मूचना देनी होगी। अब हम लोग स्टाफ की भर्ती करने के बाद कोई भी डाक्टर मध्यप्रदेश में काम करने करेगा। जहां उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, वहां जाएगा। अस्पताल डाक्टर को ज्यादा बेतन देंगे तो इसका भी अप्रत्यक्ष रूप से भार मरीज पर ही आएगा।

राज्य नागरिक आदृति नियम पर बढ़ते जा रहे कज के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने छह लाख 43 हजार टन गेहूं को नीलाम करने का फैसला किया। नियम ने पहले दो लाख टन गेहूं नीलाम करने के लिए निविदा निकाली पर शर्तों को लेकर विवाद हो गया और सरकार ने पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। इसके बाद छोटे-छोटे समूह बनाकर गेहूं नीलाम करने का कदम उठाया गया। इस प्रयास को सफलता मिली और अपनाएक हजार 875 रुपये प्रति क्रिंटल की दर प्राप्त हुई, जो समर्थन मूल्य से अधिक है। अधिकारी गेहूं की गोदामों से उत्तरव करने के लिए अनुब

